UP को मिले ₹4.26 लाख करोड़, दो रेल कॉरिडोर भी

सिटी इकॉनमिक रीजन से कई शहरों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं | केंद्रीय योजनाओं का बजट भी बढ़ा, प्रदेश में तेज होगी विकास की रफ्तार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

आम बजट से उत्तर प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर और यहां चल रही केंद्रीय योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। प्रदेश को अगले वित्त वर्ष में करीब ₹4.26 लाख करोड़ मिलेंगे। यह पिछली बार से करीब ₹25,000 करोड़ अधिक है। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए सिटी इकॉनमिक रीजन (CER) योजना का भी ऐलान हुआ है। इसके तहत पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में राजधानी जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। साथ ही सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं। दोनों कॉरिडोर बनने से दिल्ली से वाराणसी और पूर्वोत्तर भारत तक की रेलयात्रा आसान होगी। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे जुड़े सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा।

CER योजना से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। अगले पांच साल में हर सिटी इकॉनमिक रीजन के लिए करीब ₹5000 करोड़ तक का निवेश प्रस्तावित है। इससे इन शहरों और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर, स्टार्टअप हब, लॉजिस्टिक्स पार्क और सेवा क्षेत्र में विकास होगा।

बनारस में होगी जहाजों की मरम्मत: बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आसपास इंडस्ट्री का भी विकास होगा।

AI Image

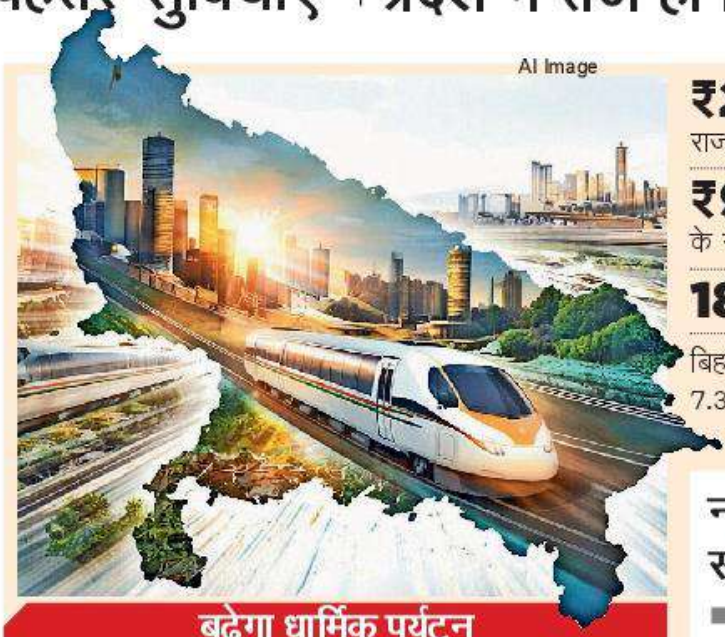

₹2.69 लाख करोड़ केंद्रीय करों के राज्यांश के तौर पर मिलेंगे

₹95,698 करोड़ इनकम टैक्स के मद में (सबसे ज्यादा)

18% हिस्सा है UP का केंद्रीय करों में

बिहार की हिस्सेदारी 10%, मध्य प्रदेश की 7.3%, महाराष्ट्र की 6.5% और राजस्थान की हिस्सेदारी 6% होगी।

बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन

सारनाथ और हस्तिनापुर देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही होटल, होम-स्टे, गाइड सेवा, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल

बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है, ताकि ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत न हो। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को बेहतर आवास सुविधा मिल सकेगी।

टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा बूम

बजट में खेल, MSME और टेक्सटाइल सेक्टर को रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। इससे मेरठ, नोएडा और आगरा के खेल उद्योग केंद्रों को लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल क्लस्टर को मजबूती देने से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कारीगरों और बुनकरों को सीधा लाभ मिलेगा।

नए और विकसित भारत की संकल्पना का बजट: योगी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को नए और विकसित भारत की सकल्पना का बजट बताया है। उन्होंने पीएम का

आभार जताते हुए कहा कि यह बजट 145 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और स्टेम (साइंस, टेक्नॉलजी, इंजिनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों की स्थापना से युवाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी।

बजट में न आम जनता का जिक्र है न फिक्र। जनता को टैक्स में छूट न देना 'टैक्स-शोषण' है। मध्यम वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। निराशाजनक, निंदनीय बजट।

-अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष